दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार 06 जुलाई 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 278

महत्वपूर्ण एवं खास

केंद्र का राजस्थान को तोहफा, गडकरी ने किया 5600 करोड़ की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपये की लागत की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। गडकरी ने मंगलवार को ट्वीट किया राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपए लागत की 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यकम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि 219 किमी लम्बी जिन चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनकी अनुमानित लागत 3,775 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा खंड तक इस 6-लेन की परियोजना से अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ खंड को 6-लेन का बनाने से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के उदयपुर, जयपुर और कोटा क्षेत्र के बीच संपर्क मजबूत होगा। फतहनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 162ए पर 4-लेन आरओबी के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। सीआरआईएफ के तहत मंडरायल में आज चम्बल नदी पर हाई लेवल ब्रिज निर्माण की शुरुआत किया गया। इस पुल के निर्माण से राजस्थान के मंडरायल, करौली और मध्य प्रदेश के सबलगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बनी रहेगी।

अब उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए नीट/सेट अनिवार्य, यूजीसी ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली (आरएनएस)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए एक अहम नोटिस जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। यूजीसी ने परीक्षा के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीके भी प्रदान किए हैं। जिन उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री है, वे परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। इसके अलावा यूजीसी की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थान भी परीक्षा के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हैं। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए जो मानदंड रखे हैं, उसके तहत उम्मीदवारों के पास कम से कम 55 % अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा मास्टर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। हालांकि, श्रेणियों के उम्मीदवारों को पांच प्रतिशत की छूट दी है। इसके अलावा उम्मीदवारों को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण होना चाहिए।

कन्हैयालाल हत्याकांड में कोर्ट ने एनआईए को दिए निर्देश, कहा- चार्जशीट की हिंदी कॉपी मुहैया कराएं

जयपुर (आरएनएस)। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विशेष अदालत ने एनआईए को निर्देश दिया है कि वह हत्याकांड के आरोपियों को उसके आरोपपत्र की हिंदी प्रति मुहैया कराए, क्योंकि उन्होंने इसे अंग्रेजी में पढऩे में असमर्थता जताई है। कन्हैयालाल हत्याकांड के गिरफ्तार नौ आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। अधिवक्ता मिन्हाजुल हक, जो दो हत्यारों, गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज़ के बिना नौ आरोपियों में से छह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कहा कि अदालत ने अभियोजक को आरोप पत्र का अनुवादित संस्करण प्रदान करने का आदेश दिया है। हक ने कहा, वास्तव में हमने दो आवेदन दायर किए हैं, पहले एनआईए आरोपपत्र के हिंदी अनुवाद का अनुरोध किया है, जो अंग्रेजी में है और दूसरे आवेदन में हमने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मांग की है। उन्होंने कहा कि अदालत बुधवार को दूसरे आवेदन के संबंध में मामले पर सुनवाई करेगी। पिछले साल जून में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ दिसंबर में विस्तृत आरोप पत्र दाखिल किया था।

बद्रीनाथ यात्रा पर मंडराने लगा खतरा : भारी बारिश से जोशीमठ में फिर पड़ने लगीं दरारें

चमोली (आरएनएस)। जोशीमठ में एक बार फिर लोगों में डर और दहशत देखने को मिल रही है। एक तरफ चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है। वहीं बरसात के सीजन में फिर से दरारों के बढऩे का सिलसिला शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को पहले ही सचेत कर दिया था कि बरसात में जोशीमठ के हाल और अधिक खराब होने वाले हैं। मगर प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और लोगों की बात न सुनने का नतीजा है कि जोशीमठ में एक बार फिर से दरारे बढ़ रही हैं और दरारों का और अधिक बढऩा लगातार जारी है जो कि बेहद चिंता का विषय है।

उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में एक बार फिर लोगों के बीच खौफ पैदा हो गया है। जोशीमठ में एक खेत में 6 फीट की गहरी दरार मिली है, जो कि माना जा रहा है कि भारी बारिश के चलते हुआ है। लोगों को डर था कि मानसून के चलते जोशीमठ में परिस्थितियां हाथ से निकल सकते हैं और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मॉनसून को शुरू हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं और जोशीमठ में दरारें और अधिक बढ़ रही हैं। इन दिनों चारधाम यात्रा जारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते में पडऩे वाला मुख्य इलाका जोशीमठ में एक बार फिर दरारों को लेकर चर्चा में आ गया है।

उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में एक चश्मदीद के मुताबिक, उसे अपने एक खेत में 6 फीट की दरार दिखाई दी। भारी बारिश के चलते ऐसा हुआ। जनवरी के महीने में कई घरों में आई खतरनाक दरारों के चलते सैकड़ों परिवारों को निकालना पड़ा था। अब जोशीमठ शहर के सुनील वार्ड के निवासी विनोद सकलानी के खेत में दरार दिखाई दी। उन्होंने कहा, मुझे अपने घर के पास एक छोटे से खेत में कम से कम 6 फीट की एक दरार मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानसून की बारिश के कारण हुआ हो।

जनवरी में एक के बाद एक कई घरों में दरारें आने लगी थीं, जिसके चलते सैंकड़ों परिवारों को सुरक्षित जगह भेजना पड़ा और घर खाली कराने पड़े। उसके बाद से ही लगातार स्थानीय लोग प्रशासन को मरम्मत का कार्य करने की अपील कर रहे थे। लोगों का कहना था कि मॉनसून आने से पहले अगर कार्य पूरा हो जाए तो दरारें आने का खतरा कम हो सकता है। मगर प्रशासन ने सुध नहीं ली। इसके बाद अब मॉनसून में दरारों का बढऩा फिर से शुरू हो गया है जो कि चिंता का विषय है।

भारत ने एससीओ बैठक में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का फिर किया विरोध

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत ने वर्चुअल एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी दिल्ली घोषणा में चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) के प्रति अपना विरोध दोहराया। घोषणा में कहा गया कि भारत को छोडक़र एससीओ के अन्य सभी सदस्य देशों ने बीआरआई को अपना समर्थन दोहराया है।

घोषणापत्र में कहा गया, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान दिया, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई के निर्माण को जोडऩे के प्रयास भी शामिल हैं।

इससे पहले एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद बीआरआई परियोजना का सीधे जिक्र किए बिना कहा था कि क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रों की अखंडता. बनाए रखना भी आवश्यक है।

मोदी ने कहा, मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है, बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है। हालांकि, इन प्रयासों में, एससीओ चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से संप्रभुता का सम्मान करना और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता।

प्रधानमंत्री ने उसी समय यह भी कहा कि एससीओ में ईरान की सदस्यता के बाद (यह आभासी शिखर सम्मेलन में समूह के नौवें सदस्य के रूप में शामिल हुआ), हम चाबहार बंदरगाह के उपयोग को अधिकतम करने की दिशा में काम कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा मध्य एशिया में भूमि से घिरे देशों के लिए हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और कुशल मार्ग के रूप में काम कर सकता है। हमें इसकी पूरी क्षमता का एहसास करने का प्रयास करना चाहिए।

पहले के मौकों पर भी, भारत ने एससीओ में बीआरआई का समर्थन नहीं किया था जबकि अन्य सदस्यों ने इस परियोजना का समर्थन किया था। एससीओ शिखर सम्मेलन वस्तुत: भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ की भागीदारी देखी गई।

अमरनाथ यात्रा : चौथे दिन 13,000 से अधिक लोगों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन

श्रीनगर (आरएनएस)। अमरनाथ यात्रा के चौथे दिन 13,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने यात्रा पूरी की, जबकि 6,107 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था बुधवार को जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा कि मंगलवार को 13,000 से अधिक यात्रियों ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए। यात्रा शुरू होने के बाद 1 जुलाई से अब तक कुल 50,000 से अधिक यात्रियों ने तीर्थयात्रा की है। अधिकारियों ने कहा, 4,680 पुरुषों; 1,203 महिलाओं; 31 बच्चों, 154 साधुओं और 39 साध्वियों सहित 6,107 यात्रियों का एक और जत्था आज सुबह 244 वाहनों के काफिले में भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ।

यात्री या तो पारंपरिक दक्षिण कश्मीर पहलगाम मार्ग से हिमालय गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं, जिसमें पहलगाम बेस कैंप से 43 किलोमीटर की चढ़ाई होती है या उत्तरी कश्मीर बालटाल बेस कैंप से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं। पारंपरिक पहलगाम मार्ग का उपयोग करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में 3-4 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का उपयोग करने वाले लोग समुद्र तल से 3888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर के अंदर 'दर्शन' करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं।गुफा मंदिर में एक बर्फ की संरचना है जिसके बारे में भक्तों का मानना है कि यह भगवान शिव की पौराणिक शक्तियों का प्रतीक है। बर्फ के स्टैलेग्माइट की संरचना चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती और बढ़ती रहती है। इस वर्ष की 62 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई और 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा उत्सव के साथ समाप्त होगी। तीर्थयात्रियों को ऊंचाई पर होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए अधिकारियों ने यात्रा के दोनों मार्गों पर स्थापित 'लंगरों' में सभी जंक फूड पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।

गुजरात दंगे से जुड़े केस में तीस्ता सीतलवाड़ को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ाई

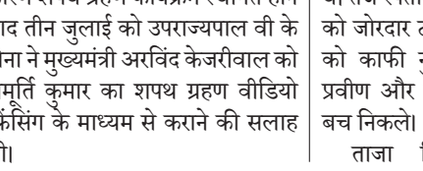

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर झेठे सबूत गढऩे से संबंधित एक मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी। जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात राज्य द्वारा स्थगन के अनुरोध के बाद नोटिस जारी करते हुए सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे तय की।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ गुजरात की तरफ से पेश हुए। उन्होंने ने कहा कि अदालत के समक्ष अतिरिक्त दस्तावेज और उनका अनुवाद दाखिल करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सीतलवाड़ की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगों के मामले में उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए झूठे दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

इससे पहले, शनिवार (1 जुलाई) को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से एक सप्ताह की राहत दी थी। सीतलवाड़ पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं। गुजरात उच्च न्यायालय ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद तुरंत आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था।

सीतलवाड को 25 जून 2022 को अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस रिमांड के बाद उसे 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

डीईआरसी अध्यक्ष शपथ टला, सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष के पद की शपथ को अगली सुनवाई 11 जुलाई तक के लिए टालने का मंगलवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने उपराज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति कुमार की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को करेगी।

शीर्ष अदालत के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि उनकी (दिल्ली सरकार) की सहमति के बिना न्यायमूर्ति कुमार को डीईआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना उपराज्यपाल का एकतरफा फैसला कानून सम्मत नहीं है। सिंघवी ने अदालत के समक्ष सवाल किया कि जब डीईआरसी के अध्यक्ष का वेतन और अन्य भुगतान दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है तो उसे (सरकार को) नियुक्ति की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

अधिवक्ता सिंघवी ने दावा किया,एक राजनीतिक कार्यकारी के रूप में मैं (दिल्ली सरकार) दिल्ली के सबसे गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली मुहैया कराता हूं। यह दिल्ली की सबसे लोकप्रिय योजना है। अब वह (उपराज्यपाल) किसी को नियुक्त करना और बिजली रोकना चाहते हैं।

सिंघवी ने दलील देते हुए यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा नियुक्ति का फैसला संविधान पीठ के फैसले और संविधान के अनुच्छेद 239-एए की भावना के खिलाफ है। उन्होंने गुरुवार को निर्धारित शपथ ग्रहण की जानकारी देते हुए पीठ के समक्ष गुहार लगाई कि वह नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना पर रोक लगाने का निर्देश दे।

शीर्ष अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने इस तथ्य पर गौर करने के बाद इस मामले पर आगे की सुनवाई करने का फैसला किया कि याचिका में केंद्र द्वारा जारी नवीनतम अध्यादेश द्वारा संशोधित जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45 डी की वैधता के बारे में कानूनी मुद्दा उठाया गया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति कुमार की नियुक्ति का समर्थन किया और किसी कारण से संबंधित मंत्री द्वारा सभापति को शपथ दिलाने में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 19 मई को शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेने के बाद नियुक्ति की गई थी।

डीईआरसी के अध्यक्ष का पद नौ जनवरी 2023 से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन के 65 साल के होने के कारण यह पद खाली है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की बिजली मंत्री आतिशी के खराब स्वास्थ्य के कारण शपथ ग्रहण कार्यक्रम स्थगित होने के बाद तीन जुलाई को उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायमूर्ति कुमार का शपथ ग्रहण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने की सलाह दी थी।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर कार हादसे का शिकार, बाल-बाल बची जान

मेरठ (आरएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार एक भीषण कार दुर्घटना में बाल-बाल बच गए हैं। इस दुर्घटना के समय कार में उनका बेटा भी मौजूद था। ये कार दुर्घटना बीती रात मेरठ में हुई थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने प्रवीण कुमार की गाड़ी में टक्कर मारी थी जिस वजह से ये दुर्घटना हुई।

जानकारी के अनुसार, ये एक्सीडेंट तब हुआ जब प्रवीण कुमार मंगलवार रात पांडव नगर से आ रहे थे। तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी जिसमें कार को काफी नुकसान पहुंचा लेकिन प्रवीण और उनका बेटा बाल-बाल बच निकले।

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया है। मेरठ के प्रवीण कुमार ने भारत के लिए 6 टेस्ट मैच, 68 वनडे मुकाबले और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। इस दौरान उन्होंने सभी फॉर्मेट मिलाकर 448 विकेट चटकाए। प्रवीण ने अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच 30 मार्च 2012 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में खेला था, वो एक टी20 मुकाबला था।

बदलेगी चंबल की पहचान, घोषित होगा डॉल्फिन अभयारण्य

आगरा (आरएनएस)। कभी डाकुओं के पनाहगार के रूप में कुख्यात चंबल की पहचान अब बदलने वाली है। सरकार इसे डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में घोषित कर पर्यटकों को आकर्षित करने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय चंबल सेंचुअरी प्रोजेक्ट की उप वन संरक्षक (वन्यजीव) आरुषि मिश्रा ने एक प्रस्ताव शासन को भेजा है।

डॉल्फिन अभयारण्य के लिए इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के सहसों क्षेत्र का चयन किया है जहां बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती हैं। आगरा में ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक और वन्यजीव प्रेमी चंबल सेंचुअरी के साथ अब जल्द ही डॉल्फिन सफारी का भी आनंद ले सकेंगे।

इटावा स्थित चंबल सेंचुरी के सहसों के 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉल्फिन पाई जाती है। यहां पर इनकी संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुअरी प्रोजेक्ट की उप वन संरक्षक (वन्यजीव) आरुषि मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन अभयारण्य का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुअरी के सहसों क्षेत्र को डॉल्फिन सेंचुरी के लिए चयन किया है। इसमें उन्होंने इटावा के सहसों का 20 किलोमीटर का दायरा चिह्नित किया है। इस स्थान पर 50 से 80 के करीब डॉल्फिन हैं। सैलानी यहां बैठकर डॉल्फिन को देख सकेंगे।

इस बार राष्ट्रीय चंबल सेंचुअरी प्रोजेक्ट के बाह और इटावा रेंज में 171 डॉल्फिन रिकॉर्ड की गई हैं जबकि साल 2012 के सर्वे में उनकी संख्या महज 78 थी।

आरुषि मिश्रा ने बताया कि साल 1979 में घोषित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 635 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश तक है। इसमें साल 2008 से घडिय़ालों की प्राकृतिक हैचिंग हो रही है। परिणाम स्वरूप उनकी संख्या भी 2,176 पर पहुंच गई है। इनके अलावा 878 मगरमच्छ के साथ उत्तर प्रदेश के इटावा तक करीब छह हजार दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। वहीं, चंबल सेंचुअरी में संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का कुनबा भी बढ़ा है।

उप वन संरक्षक ने बताया कि डॉल्फिन सफारी के लिए भारत सरकार ने दो स्थानों को प्रमुखता दी है। बीते दिनों वाराणसी और चंबल का प्रजेंटेशन भारत सरकार के सामने हो चुका है। चंबल की वास्तविक स्थिति देख सभी खुश थे। यह इको टूरिज्म और डॉल्फिन संरक्षण की दिशा में भी सरकार का बड़ा कदम है।

गौरतलब है कि गंगा नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहर सिंह ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इसके बाद से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा हर वर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि 2012 में प्रदेश की नदियों में डॉल्फिन की हुई गणना में डॉल्फिन की संख्या 671 थी, जिसमें से 78 चंबल में थीं। इस समय राष्ट्रीय चंबल सेंचुअरी क्षेत्र के बाह रेंज में 24 और इटावा रेंज में 147 डॉल्फिन हैं।